

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
संख्या: 2100/VII-II/09/141-उद्योग/2009
देहरादून: दिनांक: 13 जुलाई 2010
अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-387/697-उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांक: 2141/उ0नि0-मैगा प्रोजैक्ट/09-10 दिनांक 22 जून 2010 के संन्दर्भ में मै0 राणा एल्वाइज, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर के पक्ष में ग्राम-गंगनौली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार में मैगा प्रोजैक्ट के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचना दिनांक 29 जून 2009 से विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित भूमि के साथ उक्त ग्राम की अतिरिक्त भूमि को जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
ग्राम-गंगनौली, तहसील लक्सर,	263	1.208

- उक्त तालिका में अंकित खसरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-50/2003 सी0ई0 दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भूमि का खसरा संख्या-263 Category-B "Proposed Industrial Area/Estate" के रूप में क्रमांक-5 पर ग्राम गंगनौली, तहसील लक्सर के सम्मुख स्तम्भ-4 में अधिसूचित है। इस अधिसूचित भूमि पर स्थापित होने वाले प्रस्तावित नये उद्योग को विशेष पैकेज के अन्तर्गत आयकर छूट तथा केन्द्रीय पूँजी निवेश उपादान सहायता का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।
- GIDCR-2005- में औद्योगिक इकाई के भवन निर्माण के लिए दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पूर्णतः पालन करना होगा।
- इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।
- औद्योगिक आस्थान के रख-रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के संबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।
- विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

7. कय की जाने वाली भूमि का उपयोग "एस0एस0फलैट्स, जी0आई0पाईप, एम0एस0पाईप, एमएस0ईंगट व रिफैक्ट्री " आदि उत्पादों के विनिर्माण की इकाई की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।
8. आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।
9. विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना विशेष औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।
10. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसो शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

13/7

पृष्ठांकन संख्या: 2100 (1)/ VII-II/09/141-उद्योग/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग),
उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 राणा एल्वाइज, 4 किमी0 स्टोन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को बेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

13/7